

नेतान्याहू के आवास को निशाना लगा ड्रोन से हमला

एपी। यस्तलम

इजराइल सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री बैंजामिन नेतन्याहू के आवास की ओर शनिवार को एक ड्रोन से हमला किया गया, हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। इजराइल सरकार ने बताया कि लेबनान की ओर से गोलाबारी के मद्देनजर शनिवार सुबह इजराइल में सायरन बज उठा और इसके साथ ही प्रधानमंत्री बैंजामिन नेतन्याहू की सैसारिया स्थित आवास की ओर ड्रोन से हमला किया गया। प्रधानमंत्री के प्रवक्ता ने एक बयान में बताया कि प्रधानमंत्री आवास पर जिस समय यह हमला किया गया तब न तो नेतन्याहू और न ही उनकी पत्नी वहां मौजूद थे। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। इजराइल पर यह हमला ऐसे समय में किया गया है जब हाल के सप्ताह में लेबनान के हिजबुल्ला और इजराइल के बीच जारी संघर्ष तेज हो गया है। लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला को ईरान का समर्थन प्राप्त है। हिजबुल्ला ने शुक्रवार को कहा था कि वह इजराइल में और अधिक निर्देशित मिसाइलों और विस्फोटक ड्रोन से हमला कर उत्तरी तरफ तक जाया जाएगा।



A photograph showing three Israeli soldiers in uniform, wearing orange safety vests and hard hats, walking through a parking lot. They are carrying equipment, including a stretcher and a helmet. In the background, several cars are parked, and a person is walking away from the camera. The scene suggests a emergency response or search and rescue operation.

भी युद्ध जारी है। इजराइल के सैनिकों ने बृहस्पतिवार को हमास के शीर्ष नेता याह्या सिनवार को मार गिराया था जिसके बाद से दोनों के बीच युद्ध थमने की संभावना न के बराबर लग रही हैं इरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामोनेई ने शुक्रवार को कहा था कि सिनवार की मौत एक दुखद क्षति है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि सिनवार से पहले फलस्तीन के कई नेताओं के मारे जाने के बाद भी हमास अपना अभियान जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा था, हमास जिंदा है और जिंदा रहेगा।

उधर, इजराइल द्वारा गाजा में किए गए ताजा हमले में तीन बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ धंटे पहले किए गए एक अन्य हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए थे। फलस्तीन के चिकित्सा अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दोर अल-बलाह स्थित अल-अक्सा शहीद अस्पताल ने बताया कि इजराइल ने शनिवार सुबह मध्य गाजा में मघाजी शरणार्थी शिविर पर हमला किया, जिसमें मारे गए सभी लोग एक ही परिवार के थे।

दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला की सुरंगों के निशाना बना रहा इजराइल

प्रमुख नेता हसन नसरल्ला मारा गया तेल अवीव। गाजा में हमास के भूमिगत ठिकानों पर पिछले एक साल था, जिसके बाद इजराइल ने अक्टूबर से हमला कर रही इजराइली सेना अब दक्षिणी लेबनान में चरमपंथी समूहों की शुरुआत में लेबनान में अपनी हिजबुल्ला की भी सुरंगों और उसके अन्य ठिकानों को निशाना बना रहे सेना भेज दी थी। दूसरी ओर, है। हमास ने इजराइल में पिछले साल हमला किया था जिसके बाद इजराइल का गाजा में हमास के साथ इजराइल ने गाजा में जवाबी कार्वाई की और युद्ध शुरू हो गया। अब

इजराइल ने कहा है कि उसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उसकी उत्तरी सीमा से कोई भी ऐसा हमला या घुसपैठ न हो। इजराइली सेना ने पिछले दो हफ्तों से दक्षिण लेबनान के घने जंगलों में तलाश अभियान के दौरान एक सुरक्षा प्रणाली का पता लगाया, जिसमें हथियारों का जखीरा और रॉकेट लॉन्चर हैं। इजराइल का दावा है कि ए सुरुआती आस-

प के समुदायों के लिए सीधे खतरे का कारण बन सकती है। इजराइल कहा कि उसके आक्रमण में सीमित, स्थानीय और लक्षित जमीनी हमले मिल हैं, जिनका उद्देश्य हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करना है कि हजारों विश्वापित इजराइली अपने घर लौट सकें। लड़ाई के कारण छले महीने 10 लाख से ज्यादा लेबनानी भी बेघर हो गए। दक्षिण

के कई लोग हिजबुल्ला के समर्थक हैं। कई लोग कुछ महीने तक वहां से अपने घर छोड़कर चले गए हैं लेकिन वे हिजबुल्ला को अपना रक्षक मानते हैं। इसका कारण यह है कि लेबानी सेना के जराहिल के हमलों से उनकी रक्षा करने के लिए पार्थिव हथियार नहीं इसी लिए लोग हिजबुल्ला पर निर्भर हैं।



राष्ट्रपति द्वौपदी मुर्मू ने शनिवार को मलावी में श्री राधा कृष्ण मंदिर में पूजा-अर्चना की

भारत ने श्रीलंका के बागान समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनुदान दोगुना किया

कालबा (भाषा) भारत ने श्रीलंका में भारतीय मूल के तामिल समुदाय के बागान क्षेत्रों में शिक्षा का बढ़ावा देने के मकसद से अपने अनुदान को दोगुना करके 17 करोड़ 22 लाख 50 रुपए कर दिया है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा और श्रीलंका के शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव जे एम थिलाको जयसुंदरा ने इस अनुदान को औपचारिक रूप देने के लिए राजनयिक पत्रों पर शुक्रवार को हस्ताक्षर किए और उनका आदान-प्रदान किया। झा ने कहा, इस परियोजना के तहत श्रीलंका सरकार द्वारा चिह्नित नौ बागान स्कूल के बुनियादी ढांचे के उन्नयन की परिकल्पना की गई है। इनमें मध्य प्रांत के बागान क्षेत्रों में छह स्कूल और उवा, सबरगामुवा और दक्षिणी प्रांत में एक-एक स्कूल शामिल है। यह अतिरिक्त धनराशि श्रीलंका सरकार के अनुरोध पर दी गई और इसी के साथ इस परियोजना के लिए भारत की कुल प्रतिबद्धता अब 60 करोड़ श्रीलंकाई रुपए (17 करोड़ 22 लाख 50 भारतीय रुपए) हो गई है। यह परियोजन शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र में श्रीलंका में भारत की कई पर्यावरण एवं वर्तमान विकास साझेदारी पहलों का हिस्सा है।

पुतिन ने अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को तोड़ने के लिए समानांतर स्विफ्ट प्रणाली बनाने पर जोर दिया

मास्को> (भाषा) रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स समूह को पश्चिमी प्रतिबंधों से मुक्त स्विफ्ट जैसी सीमा-पार भुगतान प्रणाली की संभावनाएं तलाशनी चाहिए। उन्होंने साथ ही अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को खत्म करने के लिए निवेश परियोजनाओं के वित्तपोषण में राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं के इस्तेमाल पर जोर दिया। रूस की मेजबानी में आयोजित ब्रिक्स नेताओं के 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले पुतिन ने यह भी कहा कि एक साझा ब्रिक्स मुद्रा के लिए अभी समय नहीं आया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि 10 देशों का समूह डिजिटल मुद्रा के उपयोग की संभावना तलाश रहा है जिसके लिए उनका देश भारत और अन्य देशों के साथ मिलाकर काम कर रहा है।

फरवरी 2022 म यूक्रेन के साथ शुरू हुए संघर्ष के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पर व्यापक रूप से प्रतिबंध लगाए हैं। रूस ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़े वाणिज्यिक बैंकों के नेटवर्क पर आधारित एक नई भुगतान प्रणाली बनाकर वैश्विक वित्तीय प्रणाली को दरकिनार करना चाहता है। ब्रिक्स सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के ताने-बाने और स्वरूप में अंतर के कारण नई आरक्षित मुद्रा बनाने में सतर्क रुख अपनाने की वकालत करते हुए पुतिन ने कहा कि इन देशों को राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग, नए वित्तीय साधनों और स्ट्रिपट के अनुरूप एक व्यवस्था के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 22 से 23 अक्टूबर तक रूस के तातारस्तान के कजान में होने वाले इस शिखर

A formal portrait of Russian President Vladimir Putin. He is seated, facing slightly to his left, wearing a dark grey suit, a white shirt, and a dark blue tie with a subtle pattern. The background is a rich, wood-paneled room, likely the Kremlin's Hall of Mirrors.

यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने की समयसीमा निर्धारित करना कठिन

मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए कोई समयसीमा निर्धारित करना कठिन है लेकिन उन्हें यकीन है कि इसमें उनका देश जीतेगा। उन्होंने यूक्रेन में युद्ध के संबंध में प्रधानमंत्री ने रेन्ड मोदी द्वारा जताई गई चिंता को लेकर उनकी तारीफ की वजहं मिडिया से बातचीत में रूसी नेता ने कहा कि उनका देश वार्ता के पक्ष में है लेकिन इस दिशा में की गई कोशिश को यूक्रेन ने ही पलीता लगा दिया। जब पीटीआई ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें रूस और यूक्रेन के बीच शांति संबंधी वार्ता में भारत की भूमिका नजर आती है तो उन्होंने प्रधानमंत्री ने रेन्ड मोदी द्वारा व्यक्त की गई चिंता का हवाला और मोदी को मित्र बताया। पुतिन ने कहा कि रूस इसके लिए आधारी है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए कोई समयसीमा निर्धारित करना कठिन है। उन्होंने रूस को युद्ध में धकेलने के लिए अमेरिका और उत्तरी अटलांटिक संघ संगठन (नाटो) को दोषी ठहराया तथा कहा कि उनका देश विजई होगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सेना अपने बलबूते इतनी सटीकता के साथ हथियारों को लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकती है। उन्होंने कहा, यह सब नाटो पेशेवरों द्वारा किया जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि फर्क ब्याह है। नाटो हमारे खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि रूसी सेना तुनिया की सबसे अधिक प्रभावी और उच्च तकनीक वाली सेनाओं में से एक बन गई है और नाटो हमारे खिलाफ यह युद्ध लड़े-लड़ते थक जाएगा।

करने की संभावना पर विचार कर रहे हैं, और ऐसे उपकरण तैनात करना चाहते हैं, जो इसे पर्याप्त रूप से सुरक्षित बना सकें। पुतिन ने कहा कि समूह को एक टूटाकिट तैयार करनी होगी जोकि संबंधित ब्रिक्स संस्थानों की निगरानी में रहेणे उन्होंने कहा, यह हमारी प्रत्यक्ष सक्रिय भागीदारी के साथ वैश्विक दक्षिण के विकास में एक और बहुत अच्छा कदम हो सकता है। हम (कजान) शिखर सम्मेलन के दौरान इस संबंध में बहुत करेंगे। हम पहले से ही चीनी, भारतीय मित्रों व ब्राजील के लोगों के साथ परामर्श कर रहे हैं। इसके अलावा, हम दक्षिण अफ्रीका के साथ भी एक दौर का विचार-विमर्श कर चुके हैं। ब्रिक्स की संभावित मुद्रा के बारे में पतिन ने कहा कि सदस्य देशों को बिना जल्दबाजी के धीरे-धीरे काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इन देशों की आबादी और संरचना को देखते हुए, यह एक दीर्घकालिक संभावना है और अगर इन मसलों पर विचार नहीं किया गया तो यूरोपीय संघ (ईयू) में एक मुद्रा लागू करते समय हुई समस्याओं से भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा रूसी राष्ट्रपति ने केंद्रीय बैंकों के बीच संबंध स्थापित करने और वित्तीय सूचनाओं के आदान-प्रदान की जरूरत पर भी जोर दिया, जो कि अंतरराष्ट्रीय सूचना विनियम के उन अंतरराष्ट्रीय साधनों से स्वतंत्र हो, जो राजनीतिक कारणों से कृच्छ प्रतिबंध लगाते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।

ब्रिटेन की पूर्व मंत्री ने वीजा मांगों को लेकर किया भारत के साथ एफटीए रोकने का दावा

लंदन। (भाषा) ब्रिटेन की पूर्व व्यापार और वाणिज्य मंत्री केमी बेडेनोच ने दावा किया है कि उन्होंने अधिक बीज की मांग के चलते भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अवरुद्ध कर दिया था। बेडेनोच कंजर्वटिव पार्टी प्रमुख और नेता विपक्ष के रूप में त्रिव्यु सुनक कंज जगह लेने की दौड़ में सबसे आगे हैं। नाइजीरियाई मूल की बेडेनोच ने कहा कि सुनक के नेतृत्व वाली योरी सरकार द्वारा एफटीए पर हस्ताक्षर न किए जाने का एक कारण यह था कि भारतीय पक्ष प्रवासन के मुद्दे पर अधिक रियायत की अपेक्षा कर रहा था। अखबार द टेलीग्राफ के अनुसार बेडेनोच ने कहा, व्यापार मंत्री के रूप में, जब मैं प्रवासन को सीमित करने के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा थी, तब हमारे पास भारत के साथ एफटीए का मुद्दा था जिसके तहत वे प्रवासन के मामले में अधिक रियायत मांग रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। यह उन कारणों में से एक है जिसके कारण हमने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए

हालांकि, उनके कुछ पूर्व योगी मंत्रिमंडलीय सहयोगियों ने द याइम्स में बेडेनोच के दावे के विपरीत कहा कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि वह किसी भी कीमत पर समझौते के लिए जोर दे रही थीं जिससे द्विपक्षीय व्यापार साझेदारी में प्रति वर्ष 38 अरब जीबीपी की उल्लेखनीय बुद्धि होने की उमीद थी। खबर में एक पूर्व कैबिनेट मंत्री के हवाले से कहा गया, केमी किसी भी कीमत पर समझौता करना चाहती थीं और उन्हें नहीं लगता था कि जो आपत्तियाँ सामने रखी जा रही थीं, वे गंभीर थीं। इस संबंध में एक पूर्व मंत्री के हवाले से कहा गया, केमी ब्रेकिन्ट के बाद के लाभों को दिखाने के लिए एक उपलब्ध चाहती थीं और इसे हासिल करने के लिए वह उत्साहित थीं। पूर्व मंत्री ने कहा, हकीकत यह थी कि सौदेबाजी की सारी ताकत भारतीयों के पास थी और बातचीत में उनका प्रभाव हमसे ज्यादा था। हम पर सारा काम करने का बहुत ज्यादा दबाव था और वे सौदा करने के मामले में काफी

बेपरवाह थे। यहीं पर शक्ति संतुलन था और हम हमेशा कमज़ोर स्थिति से शुरूआत करते थे। हालांकि, बेडेनोच के एक करीबी सूत्र ने इस दावे का खंडन किया कि वह किसी भी कीमत पर समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कंजर्वेटिव सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर न करने का निर्णय इस उम्मीद में लिया कि वह लेबर पार्टी की सरकार के तहत बेहतर शर्तों पर बातचीत करने में सक्षम हो सकती है। भारत ने इसलिए ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि लेबर सरकार के तहत उसे छात्रों और सामाजिक सुरक्षा पर बेहतर रियायत मिलेगी। इस बीच, भारत से प्राप्त खबरों से संकेत मिलता है कि प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी सरकार के तहत एफटीए वार्ता अगले महीने शुरू होने वाली है और ब्रिटेन के अधिकारी 14 दौर की वार्ता के बाद इसमें तेजी लाने के लिए कोई समयसीमा तय नहीं कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने हैती में सभी प्रकार के हथियारों और गोला-बास्ट पर प्रतिबंध बढ़ाया

संयुक्त राष्ट्र। (एपी) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कैरेबियाई देश हैती में सभी प्रकार के हथियारों और गोला बारूद पर प्रतिवंध लगाने के लिए शुक्रवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पर मतदान किया। संयुक्त राष्ट्र ने इस गरीब कैरेबियाई देश में गिरोह द्वारा बढ़ती हिंसा और आपाधिक गतिविधियों पर भी चिंता जाहिर की। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों ने जिस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से मतदान किया, वह उसे हैती में हथियारों और सर्वेतिथि सामग्री की अवैधता तक्षकी और अन्यत्र उपयोग को रोकने के लिए उचित कदम उठाने का अधिकार देता है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा कि अमेरिका से, खासकर फ्लोरिडा से तेजी से हैती में अत्याधुनिक हथियारों की तक्षकी कर इसे सीधे ताजे पर गिरोह के सदस्यों और अपराधियों को पहुंचाया जा रहा है।

जापान की सत्ताखण्ड पार्टी के मुख्यालय पर बम से हमला, संदिग्ध गिरफ्तार

जाक्या। (एना) जापान का सत्तारूप पादों का मुख्यालय में शनिवार को एक व्यक्ति ने कई बम फेंके और प्रधानमंत्री आवास की दीवार में अपनी कार से टक्कर मार दी। तोक्यो पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध हमलावर की पहचान 49 वर्षीय अत्युदाहरणीय उसुदा के रूप में की गई है और उसे सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हालांकि स्पष्ट किया कि बाद में उस पर अतिरिक्त आरोप भी जोड़े जा सकते हैं हमले का मकसद तत्काल स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जापानी मीडिया की खबरों के मुताबिक सोशल मीडिया पर उसुदा की एक कथित पोस्ट है जिसमें वह जापानी कानून के तहत चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक धनराशि के बारे में शिकायत कर रहे हैं,

